प्रदेश में वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम

वित्तीय साक्षरता क्यों आवश्यक है:-वर्तमान परिदृश्य में देखा जा रहा है कि आम नागरिकों में अपनी आमदानी और खर्चो का प्रबंधन करना और बचत के प्रति समज विकसित नही है। यही कारण है कि अपनी आमदानी खर्च और बचत का लेखा-जोखा रखना और आमदानी, का उचित नियोजन करना नही आता है, साथ ही लोग गैर जरूरी खर्चो को ज्यादा कर देते है। जब उन्हें पैसों की वास्तविक आवश्यकता रहती है तो उनके पास पैसे ही नही रहते है। उन्हें बचत कैसे क्यों और कहॉ-कहॉ करना चाहिए, इस जानकारी की कमी प्रतीत हो रही है।

दैनिक जीवन में आम नागरिकों को आ रही परेशानियों को देखते हुए बच्चों में आमदानी और खर्च का प्रबंधन करना और बचत के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रदेश के बच्चों को वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

वित्तीय साक्षरता हमें आमदानी और खर्च का उचित प्रबंधन सिखाती है

वित्तीय साक्षरता क्या है:- वित्तीय साक्षरता हमें अपनी आमदनी का उचित प्रबंधन करने के लिए रास्ता बताती है। इससे हमें निम्नलिखित बिन्दुओं की जानकारी प्राप्त होती है:-

- अपनी आमदनी का उचित नियोजन कर सकेंगें।
- गैर जरूरी खर्चो में कटौती कर सकेंगे।
- बचत की आदत डाल सकेगें।
- वित्तीय संस्थाओं के बारे में जान सकेगें।
- अनुत्पादक ऋण लेने से बच सकेगें।
- अपनी बचत का उचित उपयोग करने के बारे में जान सकेगें।
- वित्तीय संस्थाओं के बारे में जानकारी और उनसे कैसे जुड़ना, उस प्रक्रिया की जानकारी दी जावेगी।
- डिजिटल प्रणाली के संबंध में जानकारी देना।

उपरोक्त बिन्दुओं पर प्रदेश के समस्त शासकीय माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सैकेण्डरी शालाओं में दर्ज कक्षा -06 से कक्षा - 12 तक के बच्चों को स्कूलों में वित्तीय प्रशिक्षण कार्यक्रम स्कूल शिक्षा विभाग एवं भारतीय रिर्जव बैक के समन्वय से वित्तीय शिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। शिक्षा संस्थानो के छात्र/छात्राओं को धनराशि हस्तांतरण के लिये डिजिटली रूप से सक्षम, नगद रहित आर्थिक प्रणाली का उपयोग करने के लिये सभी प्रदाताओं और प्राप्तकर्ताओं को प्रोत्साहित और पे्ररित करना है। मध्यप्रदेश शासन नें शिक्षा संस्थानो और छात्रो को इस परिवर्तनकारी बदलाव में खर्च का प्रबंधन करना और बचत के प्रति जागरूक रहने के लिये वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण दिये जा रहे है

वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत वित्तीय समावेश और विकास विभाग, भारतीय रिर्जव बैक भोपाल एवं स्कूल शिक्षा विभाग के साथ 31 अक्टूबर 2018 को राज्य शिक्षा केन्द्र में बैठक आयोजित हुई, और प्रशिक्षण के संबंध में दिनॉक 05 दिसम्बर 2018 को मंत्रालय से एक विडियो कानफ्रेसिंग का आयोजन किया गया। जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक एवं सभी अग्रणी जिला अधिकारी (एल.डी.एम) एवं सभी सहायक परियोजना समन्वयको को कार्यक्रम के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। दिनॉक 06 दिसम्बर 2018 को ही जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक एवं सभी अग्रणी जिला अधिकारी (एल.डी.एम) द्वारा अपने अपने जिले से समस्त शालाओं के लिए गतिविधि कलैण्डर तैयार किया गया।

प्रदेश में लगभग 32,000 मिडिल स्कूल तथा 8,800 हाईस्कूल एवं हायरसेकेण्डरी स्कूलों को वित्तीय प्रशिक्षण दिये जाने की कार्ययोजना तैयार की गई। अग्रणी जिला अधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयकों द्वारा जिलों के समस्त स्कूलों में वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण देने के लिए सभी बैंक शाखाओं को आवंटित किया गया। जिला सिहोर को सर्व प्रथम पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में चयन किया गया और जिले के समस्त शासकीय माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायरसेकेण्डरी स्कूलों में कैम्प लगाकर वित्तीय प्रशिक्षण दिया गया।

वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण में बताया की बैंक में बचत खाता, वीसा ऋण, प्रधानमंत्री बीमा योजना, बचत के खाते शून्य खाता संचालित करने तथा किस प्रकार से फटे-पुराने नोटो को बैंक से बदलवाया जा सकता है, ऑनलाईन बैकिंग की उपयोगिता एवं इसमें हो रही (धोखाधडी) फ्राड से कैसे बचा जा सकता है इस पर विस्तृत चर्चा की गई।

इस प्रकार अनेक यादगार पल वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण में समस्त माध्यमिक/हाई स्कूल एवं हायरसेकेण्डरी विद्यालय में आये। इस प्रशिक्षण से पूर्व छात्रो को बैकिंग की कार्यप्रणाली से संकोच होता था परन्तु इस प्रशिक्षण के बाद वह बैकिंग के साथ फ्रैंडली हो गये है। इस प्रशिक्षण के दौरान सभी छात्र काफी उत्साहित नजर आये। और इन छात्रों के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर नवसाक्षरों एवं अपने पालकों को भी घर में जाकर प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी दी गई।

अभी तक प्रदेश में लगभग 15,500 कैम्पों का आयोजन किया गया इसमें एक बात का ध्याान दिया गया जहॉ आस-पास माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल है। उन सभी बच्चों को एक साथ बैठाकर वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण दिया गया। 20 जून से 31 जुलाई 2019 के मध्य प्रदेश के समस्त माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में दर्ज बच्चों को एकबार प्रशिक्षण दिये जाने की कार्य योजना है। साथ ही प्रत्येक 03 माह में इन बच्चों का फोलोअप के रूप में प्रशिक्षण दिये जाने का प्रयास किया जावेगा।